

कर्नाटक में हजाब पर प्रतर्बिंध मामला

प्रलिमिंस के लयि:

सर्वोच्च न्यायालय, हजाब, मौलिक अधिकार, धरुड की स्वतंत्रता से संबंधित मामले ।

मेनुस के लयि:

मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, सरकारी नीतयिँ और हस्तक्षेप, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, धरुड की स्वतंत्रता से संबंधित मामले ।

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने कर्नाटक हजाब प्रतर्बिंध मामले में एक वभिजति नरिणय दयिा ।

- वभिजति नरिणय की स्थिति में मामले की **सुनवाई एक बड़ी बेंच द्वारा** की जाती है ।
- जसि बड़ी बेंच को वभिजति नरिणय का मामला हस्तांतरित कयिा जाता है, वह **उच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ** हो सकती है, अथवा इस संबंध में **सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी अपील** की जा सकती है ।
- **मार्च 2022** में उच्च न्यायालय ने कर्नाटक में मुसलमि छात्रों के एक वर्ग द्वारा कक्षाओं में हजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को इस आधार पर खारजि कर दयिा था कयिह **इस्लामी आस्था में आवश्यक धारुडिक प्रथा का हसिंसा नहीं है** ।

A timeline of the legal battle

The row, which erupted when a Udupi college barred hijab-clad students from entering classrooms, soon garnered national attention and reached the SC.

2021: Row begins
JULY 1: Govt Pre-University (PU) college in Udupi issues guidelines for the academic year, prescribes a uniform code

DEC 28: Six students claim that, since Sept, they are not being allowed entry into classrooms, citing hijabs

2022: Matter reaches Karnataka HC
JAN 31: Students move HC against college's guidelines

FEB 5: State issues an order allowing only prescribed uniforms in govt colleges

FEB 10: HC passes interim order, prohibiting students from wearing religious clothing till the matter is decided

OCT 13: SC delivers split verdict, directs placing appeals against HC order before CJJ for constitution of larger bench

SEPT 22: SC reserves its order on the pleas

Students move Supreme Court
JAN 31: Students move HC against college's guidelines

MARCH 15: HC rules hijab is not an intrinsic part of Islam, upholds the state govt's order

FEB 17: Fresh plea in HC seeks nod to wear hijabs in educational institutes on Fridays and during Ramzan

WHAT THE BJP SAYS

At a time when there is a movement against hijab and burqa across the globe and the freedom of women is a talking point, the K'taka govt expected a better judgment...
 — **BC NAGESH**, K'taka education minister

WHAT THE OPPN SAYS

After banning the hijab, around 17,000 first generation students were out of schools. The government has succeeded in its plans to not educate these girls.
 — **BK HARIPRASAD**, Cong LoP in K'taka

नरिणय की प्रमुख बातें:

Divergent views



A look at what was emphasised by the two verdicts on the hijab ban

DELIVERED BY JUSTICE HEMANT GUPTA

"Secularism is applicable to all citizens, therefore, permitting one ... community to wear their religious symbols would be antithesis to secularism."

SCHOOL AND RELIGION: Religion has no meaning in a secular school run by the state. "Students are free to profess their religion and carry out religious activities other than when they're attending a classroom."

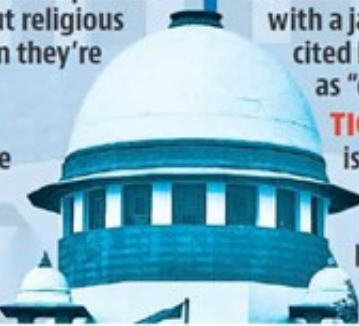
UNIFORM, EQUALITY: "... Uniform fosters a sense of 'equality' amongst students- instills a sense of oneness, diminishes individual differences..."

DELIVERED BY JUSTICE SUDHANSHU DHULIA

"Wearing hijab should be simply a matter of choice. It may or may not be a matter of essential religious practice, but it still is, a matter of conscience, belief, expression."

CLASSROOM IS DIFFERENT: Though discipline is required in educational institutions, they can't be put on par with a jail or a military camp, as was cited by HC while describing schools as "qualified public spaces"

TICKET TO EDUCATION: "If it is worn as a matter of her choice, as it may be the only way her conservative family will permit her to go to school... her hijab is her ticket to education"



हजिाब के मुद्दे पर न्यायालयों के अब तक के नरिणयः

- वर्ष 2015 में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी दो याचिकाएँ दायर की गई थीं, इनमें अखलि भारतीय प्री-मेडिकल प्रवेश के लिये ड्रेस कोड को चुनौती दी गई थी, जसिमें सलवार/पायजामा" के साथ चप्पल पहनने की अनुमति थी एवं आधी आस्तीन वाले हल्के कपड़े, जनिमें बड़े बटन, बैज, फूल आदि न हों", ही पहनने का प्रावधान था।
 - केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के तरक को स्वीकार करते हुए कयिह नयिम केवल यह सुनश्चिति करने के लयि था कि उम्मीदवार कपड़ों के भीतर वस्तुओं को छुपाकर अनुचति तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केरल उच्च न्यायालय ने CBSE को उन छात्रों की जाँच हेतु अतरिकित उपाय करने का नरिदेश दिया जो अपने धार्मिक रविाज के अनुसार पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं, लेकिन जो ड्रेस कोड के वपिरीत हैं।
- आमना बटि बशीर बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (2016) मामले में केरल उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे की अधकि बारीकी से जाँच की। इस मामले में न्यायालय ने माना कि हजिाब पहनने की प्रथा एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, लेकिन सीबीएसई नयिम को रद्द नहीं कयिा गया।
 - न्यायालय ने एक बार फरि 2015 में "अतरिकित उपायों" और सुरक्षा उपायों की अनुमति दी।
- हालाँकि स्कूल द्वारा नरिधारति ड्रेस के मुद्दे पर एक और बेंच ने फातमिा तसनीम बनाम केरल राज्य (2018) मामले में अलग तरीके से फैसला सुनाया।
 - केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कहा कि कसिी संस्था के सामूहिक अधिकारों को याचकिाकर्त्ता के व्यक्तगत अधिकारों पर प्राथमकिता दी जाएगी।

संवधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षाः

- संवधान के भाग-3 (मौलिक अधिकार) का अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।
- संवधान का अनुच्छेद 25 (1) 'अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार' की गारंटी देता है।
- यह एक ऐसा अधिकार है जो नकारात्मक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जसिका अर्थ है कि राज्य यह सुनश्चिति करेगा कि इस स्वतंत्रता का उपयोग करने में कोई हस्तकषेप या बाधा न हो।
 - हालाँकि सभी मौलिक अधिकारों की तरह राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य राज्य हतियों के अधिकार को प्रतर्बिधति कर सकता है।
- अनुच्छेद 26 सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता की व्याख्या करता है।
- अनुच्छेद 27 के अनुसार, कसिी भी व्यक्त को कसिी वशिष धर्म के प्रचार या व्यवहार के लयि कसिी भी कर का भुगतान करने के लयि मजबूर नहीं कयिा जाएगा।
- अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता की व्याख्या करता है।

आगे की राह

- मौजूदा राजनीतिक माहौल में कर्नाटक सरकार द्वारा "एकता, समानता एवं सार्वजनिक व्यवस्था के हति में" या तो एक नरिधारति वर्दी या कसिी भी पोशाक को अनविरय करने के नरिणय को शैक्षणिक संस्थानों में धर्मनरिपेक्ष मानदंडों, समानता और अनुशासन को लागू करने की आड में एक बहुसंख्यकवादी दावे के रूप में भी देखा गया।
- एक नरिणय जो शिक्षा के लयि इस गैर-समावेशी दृष्टिकोण को वैध बनाता है और एक नीति जो मुस्लिम महिलाओं को अवसर से वंचति कर सकती है, देश के हति में नहीं होगी।
- उचति गुंजाइश तब तक होनी चाहयि जब तक कि हजिाब या कोई भी पहनावा, धार्मिक या अन्य, यूनफार्म से अलग नहीं होता है।

स्रोतः द हद्रि